Hkkjrh; turk ikVÊ

(केन्द्रीय कार्यालय)

11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

फोन नं. : 23305700, **फैक्स** : 23005787

दिनांक : 18 सितम्बर, 2009

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा संसद सदस्य श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

भाजपा की मांग है कि भारत–चीन संबंधों के समूचे आयामों पर एक श्वेत–पत्र जारी किया जाए

गत कुछ महीनों के दौरान भारत की सीमा पर चीनी घुसपैठ की घटनाओं में बहुत ही चिंताजनक तथा अशुभ वृद्धि हुई है। विश्वसनीय सूचना के अनुसार वर्ष 2008 में 233 बार चीनी घुसपैठ हुई तथा गत तीन महीनों के दौरान 76 बार घुसपैठ हुई। इसमें न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन शामिल है बल्कि, चीन की सेना द्वारा भारत के भू–क्षेत्र में घुस आने का और अनेक बार हेलीकॉप्टर द्वारा अतिक्रमण करना शमिल है। जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तब यह जानकर व्यथा होती है कि जिन लोगों के कंधों पर हमारी विदेश नीति को प्रबंधित करने का भार है, वे सादगी दर्शाने की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में उलझे हुए हैं तथा वे भारत के मध्यम वर्ग को पशु वर्ग के रूप में चित्रित कर रहे हैं। ये ऐसी बातें है जिनकी घोर निंदा की जानी चाहिए।

चीनी घुसपैठ न केवल लद्दाख या उत्तर पूर्वी क्षेत्र – विशेषतया अरूणाचल प्रदेश में, बल्कि अब ये सिक्किम के आस–पास भी हो रही है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि राजग शासनकाल के दौरान चीन ने सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा स्वीकार कर लिया था। यह बेहद कष्टदायक और हैरानी पैदा करने वाली बात है कि भारत सरकार इसकी जान–बूझकर अनदेखी कर रही है तथा विदेश मंत्री ने इस तथ्य के बावजूद इसको सार्वजनिक रूप से मामूली घटना बताया है कि चीन के आक्रामक रवैये के पीछे कुत्सित इरादे और उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित से साफ प्रकट होते हैं :

1. चीनी राजदूत ने अरूणाचल प्रदेश को बार–बार विवादित क्षेत्र घोषित किया है, जिसको चीनी नेताओं ने भी समय–समय पर पुनरूक्त किया है।

2. चीन अरूणाचल प्रदेश में तवांग पर इस आधार पर विशेष रूप में दावा करता है कि छठे दलाई लामा का जन्म वहीं हुआ था। साथ ही चीन वर्तमान दलाई लामा के भारत दौरे का भी सख्त विरोध करता है। भाजपा दलाई लामा के दौरे का पूरी तरह समर्थन करती है।

3. जब भी कोई भारत का वरिष्ठ राजनैतिक नेता – यथा प्रधानमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति भी अरूणाचल राज्य का दौरा करते हैं तभी चीन हमेशा इसका विरोध करता है।

4. अब अरूणाचल प्रदेश के तथाकथित विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिए जाने के जान–बूझकर कुत्सित इरादें व्यक्त किए जा रहे हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि चीन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के माध्यम से एशिया विकास बैंक को यह स्वीकार न करने देने में सफल हो गया था कि अरूणाचल प्रदेश भारत का भाग है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि चीनी प्रधानमंत्री के विगत दौरे के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि हर मुद्दे को द्विपक्षीय

रूप में सुलझाया जाएगा। यहां तक कि, भारत के पारंपरिक मित्रों जैसे जापान आदि ने भी भारत के हितों के विरूद्ध मत दिया था।

5. वार्ता (ढांचागत या अन्यथा) के कई दौरों का भी कोई परिणाम नहीं निकला है।

6. चीन तथा पाकिस्तान दोनों के द्वारा सीमा के उल्लघन में एक समय पर वृद्धि की गई है, जो भारत के विरूद्ध चिंताजनक टीम वर्क दर्शाता है।

7. हाल में चीनी थिंक–टैंक द्वारा एक लेख छापा था कि चीन की सामरिक सुरक्षा के लिए भारत को बीस अलग–अलग देशों में विघटित किए जाने की जरूरत है। चीनी स्थापना ने इसका कोई स्पष्ट खंडन नहीं किया था।

8. अतिवादी समूहों विशेषकर उल्फा को चीन के समर्थन की रिपोर्ट लगातार मिलती हैं।

इन सब बातों का संचयी संकेत वाकई अशुभ और परेशान करने वाला है। फिर भी सरकार का पूरा रवैया घोर उपेक्षाभरा बना हुआ है। इस घटनाक्रम को कम आंकने के जान–बूझकर प्रयास क्यों किए जा रहे हैं ? चीन के साथ संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है ? ये भटकाव और विचलन क्यों किया जा रहा है ? क्या सरकार इस भटकाव को काबू में करने में अक्षम है ? 1962 के कडुवे अनुभव के संदर्भ में देश को यह सब जानने और आश्वस्त होने का हक है। भाजपा बातचीत का तथा संबंधों के सामान्यीकरण का समर्थन करती है किंतु ऐसा जानबूझकर जमीनी हकीकत की, बार–बार की धमकियों की अनदेखी करके और भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर सौदेबाजी करके नहीं किया जाना चाहिए।

मांगें

तदनुसार भाजपा की मांग है कि भारत सरकार भारत–चीन संबंधों के पूरे आयामों पर तत्काल एक श्वेत–पत्र प्रकाशित करे, जिसमें सीमा पर हमारी तैयारी के बुनियादी ढांचे को सुधारा जाना तथा सुदृढ़ किया जाना शामिल हो। आज यह याद किए जाने की जरूरत है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल के कारण भारत सरकार से 1962 में तैयारी न किए जाने के कारण हुई अपमानजनक पराजय के बारे में श्वेत–पत्र प्रकाशित करने पर जोर नहीं दिया गया था। भाजपा यह मांग भी करती है कि देश को इस बारे में विश्वास में लिया जाए कि किस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं और सरकार उन्हें किस रूप में लेती हैं तथा वह देश की सुरक्षा के बारे में क्या सुधारात्मक उपाय कर रही है। ऐसा करना सादगी और ट्वीटिंग की राजनीति से कहीं अधिक जरूरी है।

¼';ke tkt½
मुख्यालय प्रभारी